कृषि क्षेत्र में बेहतरी की उम्मीद

प्रो. संजीव पराशर
डीन अकादमिक एवं
प्रोफेसर मार्केटिंग,
आईआईएम रायपुर

बहुआयामी चुनौतियों के बावजूद बजट संतुलित प्रतीत होता है। बजट की धुरी रोजगार और समावेशी विकास है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और बढ़े हुए खर्च के मध्य बजट में संतुलन की कोशिश की गई है। कृषि और सिंचाई की स्थितियों में सुधार के लिए 16 कदमों के साथ, सरकार ने इन गतिविधियों के लिए कुल बजट का लगभग 5% आवंटित किया है। इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बजट कुल बजट का लगभग 10% है। कदमों में उर्वरकों का अनुकूलित उपयोग शामिल है, जैविक खेती से सामान्य कल्याण होगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग होगा, जो किसानों को सौर पैनलों के माध्यम से बिजली उत्पादन करने के लिए अपनी बंजर भूमि का उपयोग करने में मदद करेगा और आय में वृद्धि करेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में आसान बाजार पहुंच की सुविधा के लिए किसान रेल और कृषि उद्योग की शुरुआत के माध्यम से कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है।

बजट में ब्लॉक/तालुका स्तर और स्व-सहायता समूहों के लिए गोदामों की स्थापना के लिए प्रावधान दिया गया है। इससे उन्हें सहायता मिलेगी, क्योंकि भंडारण की कई तरह की दिक्कतें होती हैं, विशेषकर भंडारण प्रणाली में। धनलक्ष्मी की पारंपरिक अवधारणा पर जोर दिया गया है। नाबार्ड की बैंडविड्थ को भी बढ़ाया गया है। राज्य सरकारों की सहायता लेते हुए जिला स्तर पर बागवानी समूहों के गठन का भी प्रस्ताव है। 2024-25 तक मत्स्य उत्पादों के निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। मछली, किसान उत्पादक संगठनों के व्यापक नेटवर्क से सुदृढ़ होंगे।

बजट शिक्षा और उद्योग के बीच निर्माण पुलों के बारे में भी बात करता है। पैरामेडिक्स, शिक्षक, नर्स और केयरटेकर्स के लिए पुल कोर्स प्रस्तावित है। इनकी भारी मांग रही है। रोजगार बढ़ाने के प्रशिक्षुता, डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम का भी प्रस्ताव है। इंटर्नशिप के अवसर इससे बढ़ेंगे। शीर्ष 100 एनआईआरएफ रैंक वाले संस्थान ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रम भी प्रदान कर सकते हैं, जो न केवल आउटरीच बढ़ाएगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता भी बनाए रखेगा। बजट में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

Haribhoomi, 2nd Feb 2020,p.8